RAJYA SABHA

Thursday, the 14th May, 1992/24 Vaisakha, 1914

The House met at eleven of the Clock Mr. Chairman in the Chair

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

CBI enquiry into irregularities in the selection of sponsored T.V. serials

*241. SHRI VITHALPHAI M. PATEL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to refer to the answer to Starred Question 64 given in Rajya Sabha on 30th April, 1992 and state:

(a) what are the terms of reference of the CBI enquiry into the irregularities in the selection of sponsored T.V. Serials;

(b) whether any time limit has been given to CBI to submit its report;

(c) whether Government are considering cancellation of the cleared sponsored serials after detection of irregularities by the C.B.I.;

(d) whether Government have any pending sponsored serials to be telecast; and

(e) if so, the number of such sponsored serials which are yet to be telecast by the Doordarshan?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIJA VYAS): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

CBI enquiry into irregularities in the selection of sponsored serials

(a) to (c) Investigations relating to reported irregularities and illegalities in the purported approval of proposals under New Sponsorship Scheme 1990 of Doordarshan have been entrusted to the CBI. They have been requested to take up the case as a special inquiry and to complete it as expeditiously as possible. Communication of the final result regarding the proposals received under the said New Sponsorship Scheme of 1990 has been kept in abeyance.

(d) and (t) Thirty two sponsored serials with varying number of episodes are lined up for telecast by Doordarshan.

श्री विठ्ठलभाई मोती राम पटेल: सभापति महोदय, मैंने जो सवाल मंत्री जी से पूछा था, उन्होंने मेरे सवाल का पूरा जवाब नहीं दिया है। मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने यह बताया है कि भ्रष्टाचार हुआ है। आप जब कहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है तो उन्होंने सी० बी०आई० को क्या जांच करने के लिए कहा है। मैंने यह साफ तौर पर पूछा है कि What are the terms of reference of the CBI enquiry into the irregularities in the selection of sponsored T.V. serials? इस प्रश्न का उन्होंने जवाब नहीं दिया। केवल इतना ही कहा है कि सी०बी०आई० को हमने जांच करने के लिए भेज दिया है। अब सवाल यह है कि सी०बी०आई० क्या जांच करेगी, क्या भ्रष्टाचार की जांच करेगी या सीरियल कैसे सेलेक्ट किया गया है या नहीं किया गया है, आप यह बताइये कि वह क्या जांच करेगी। इन्होंने जो कमेटी बनाई थी उसमें ऐसे लोग रखे हैं

Those who are connected with the production of serials, those who are script-writers, majority of them are retired officer of Doordarshan, their wives and their sisters. Such people are nominated to select the serials. They have selected 400 serials which they wanted. But the remaining 3,100 serials have not been read at all. They do not read the scripts. Some of them have not even been opened. In these circumstances, what is the Minister going to do about the 3,100 applicants, who have paid Rs. 2,000 to Doordarshan, who have spent Rs. 15,000 to Rs. 20,000 for writing of the script? Now they are asking them

to appeal by paying Rs. 3,000. Why should they be punished? The wrong has been done by the members of the Committee. They have selected the serials. (*Interruptions*)

श्री सभापति : अब सवाल हो गया है।

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : 3100 का क्या करेंगे और आपने रेफेंस क्या किया है सी०बी०आई० को ?

What are the terms of reference to the CBI?

MR. CHAIRMAN: He wants to know the terms of reference of the CBI enquiry and regarding those who have already submitted their applications, why is the department asking them to give Rs. 3,000? (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI AJIT KUMAR PANJA): Sir, in the question itself.... (*Interruptions*)

SHRI SUKOMAL SEN: Sir, today is the Prime Minister's da yand he is not present. The Prime Minister should be present here. (*Interruptions*)

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, the absence of the Prime Minister yesterday was understandable. But today it is obligatory on his part to be present. (*Interruptions*)

SHRI DIPEN GHOSH: For the last two Thursdays, we have been raising this issue. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: There is a Minister sitting. (*Interruptions*)

श्री प्रमोद महाजन : प्रधानमंत्री जी एक दिन सप्ताह में आते हैं और उस दिन भी न आएं तो **(व्यवधान)**

श्री अजीत जोगी : आपको अपने प्रश्नों का जवाब मिलेगा **(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन : अगर आ जाएं तो आपको भी उनके दर्शन हो जाएंगे **(व्यवधान)**

MR. CHAIRMAN: When it comes to his question, we will see. (*Interruptions*)

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, he was hiding himself in the Lobby. It is not fair. (*Interruptions*)

श्री शंकर दयाल सिंह : प्रधानमंत्री जी तक हमारी आवाज चली गई और प्रधानमंत्री जी आ गये। **(व्यवधान)** अब मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि वे अपने मंत्रालय के प्रश्नों का उत्तर दें **(व्यवधान)** यही मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : आपने पुकारा और हम चले आए **(व्यवधान)**

श्री सभापति : असल में ये जो जयपाल रेड्डी हैं इन्होंने पहले से बात कर रखी थी कि जब मैं शोर करूं तो आप आ जाएंगे। तेलुगू में बात की थी इसलिए अपने को समझ में नहीं आया।

SHRI AJIT KUMAR PANJA: Sir, as soon as the name of our Prime Minister was taken, he entered. The whole House wishes that our Prime Minister should live long, as the saying goes in Bengali... (*Interruptions*)...

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, the Prime Minister always remains permanent... (*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: But he entered.

SHRI AJIT KUMAR PANJA: So far as the hon. Member's question is concerned, he himself indicated, while asking the question, many irregularities, some of which the CBI will also be enquiring into. When a matter is sent to the CBI, there is nothing called "terms of reference". There is a distinction between the functioning of an Inquiry Commission and the CBI. In the case

of an Inquiry Commission, like the Verma Inquiry Commission that is going on terms of reference are given. But so far as the CBI is concerned, a letter is given by the Government saying that these are the allegations which have been received and the Government *prima facie* has found that it is a matter for inquiry. Therefore, we have thought that a specialised agency should be entrusted with this inquiry. An allegation has been made against a Central Government servant, that is why it is handed over to the CBI. So far as the names of the members of the Committee are concerned, no one has made any allegation, as per my knowledge, regarding the members of the Committee. But if any allegation is made, certainly the CBI will go into that also. Nothing is limiting the CBI from making an inquiry

MR. CHAIRMAN: What about those three thousand rupees?...(*Interruptions*)..

SHRI AJIT KUMAR PANJA: It is a separete thing. Sir, earlier the provision was not there. When somebody's serial was rejected, (a) no reason was given previously and (b) he had no other forum to agitate the point. We have found that reasons have to be given as to why the serial has been rejected and there must be another forum of a separate Committee Member before whom the person can file an appeal, otherwise, that citizen is not having a chance to make any appeal whatsoever and the serial is rejected at the first instance...

SHRI JAGESH DESAI: An appeal provision is there now.

SHRI AJIT KUMAR PANJA: That is why an appeal provision has been made and to see that the Commission is not misused, a sum of about Rs. 2,000/- is fixed as fee for filing an appeal. This is the provision. That stage has not yet come because the first approval has not yet come.

श्री विट्ठलभाई मोतीराम पटेल : सभापति जी, मंत्री महोदय को खुद को पता नहीं है कि 3,100 बाकी है। किसी ने पढ़े ही नहीं हैं। इससें आधे नहीं पढ़े हैं। स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है किसी ने।

श्री सभापति : आपने तो पढ़ी है।

श्री विट्ठल भाई मोती राम पटेल : मुझे सब का तो पता नहीं है। कुछ का पता है कि अच्छे सीरियल हैं। उनको भी उन्होंने रिजेक्ट किया है। ये फिर पढ़ने के लिए दूसरी कमेटी बनाये और उससें व्यग्रर्स को रखें।

श्री सभापति : आप प्रश्न कर लें।

श्री विट्ठल भाई मोती राम पटेल : व्यग्रर्स असोसिएशन टी०वी० देखने वालों का कई शहरों में है। जो टी० वी० देखने वाले हैं उनमे से कुछ लोगों को रखिए स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए क्योंकि देखने वाले वे हैं। वे कहेंगे अच्छा क्या है बुरा क्या है।

दूसरा, इससें भष्टाचार तो हुआ है। पैसा जिसने दिया उसका सीरियल पास किया। जिसकी एप्रोच नहीं है।

श्री सभापति : इसीलिए जांच करा रहे हैं। आप प्रश्न कर लें।

श्री विट्ठलभाई मोतीलाल पटेल : जिसकी एप्रोच नही है उनका कुछ नहीं किया।

तीसरा यह है कि जो सीरियल क्लियर नहीं किये हैं उनको आप कैंसिल क्यों नहीं करते हैं। जो चार सौ साढ़े चार सौ क्लियर किये हैं वे करप्शन से क्लियर किये हैं। ये सब कैंसिल करके नये सिरे से फिर आप दूसरी कमेटी बना कर क्या पूरे सीरियल की जांच कराएंगे अगर नहीं कराएंगे तो क्यों नहीं कराएंगे?

कुमारी गिरजा व्यास : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य महोदय ने

अपने आप अभी कहा कि करीब 34 मेम्बर्स हैं जिनकी करीब 34 सब-कमेटीज थीं। उनकी 237 मीटिंगें हुई और उसमें उन्होंने निर्णय लिये। अभी अभी जैसे महोदय ने कहा, हमें कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिससे किसी मेम्बर के संबंध में कुछ गलत कहा गया हो, फिर भी सारा का सारा मसला सी.बी.आई. के पास है। जहां तक आपका दूसरा...

श्री विठ्ठलभाई मोती रामपटेल : यह लिस्ट है आपकी इसमें आप देखिए, दूरदर्शन के रिटायर्ड आफिसर हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनकी बहिनें हैं।

श्री सभापति : आप सी०बी०आई० को सब बता दीजिएगा।

कुमारी गिरिजा व्यास : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने जो दूसरा प्रश्न उठाया है कि...

श्री सभापति : मंत्री जी को यह नहीं पता है, हरेक की पत्नी का हिसाब थोड़े ही रखते हैं मंत्री।

कुमारी गिरिजा व्यास : जो अभी तक क्लिअर हो गए हैं, उन्हें हम लोगों ने रोका, उसको रोकने का कुछ भी उत्तरदायित्व हम पर नहीं है क्योंकि सारा मसला सी०बी०आई० के पास है। जहां तक आपका तीसरा प्रश्न है कि कुछ लोगों को कमेटी में रखने का सुझाव आपने दिया, उसको नोट कर लिया गया है।

श्री शंकर दयाल सिंह : सभापति जी, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि दूरदर्शन के द्वारा और धारावाहिकों के द्वारा देश का एक बहुत बड़ा भाग इससे संबद्ध है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं पहली बात तो यह कि जो सी०बी०आई० इक्वायरी आपने दी है, उसके अंतर्गत कुछ ऐसे सीरियल्स हैं जोकि निर्विवाद रूप से इस परिधि में नहीं आते हैं, उनको मंजूरी देते हुए जिनके ऊपर आपत्ति है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है उनके संबंध में जांच करवाएं। दूसरी बात यह है कि क्या इसमें मंत्री महोदय द्वारा भी दखलंदाजी की गयी है और सी०बी०आई० क्या उन चीजों की भी इंक्वायरी करेगी और अंतिम बात यह कि आखिरी प्रश्न के मुताबिक यह जो चाणक्य का सीरियल चल रहा है जिसके कि बारे में कई बार इस तरह की बातें आती हैं कि इसकी कड़ियां कम कर दी गयी हैं और यह भी इसमें आया है कि प्रधान मंत्री महोदय को भी इसके बारे में जब अप्रोच किया गया और कहा गया तो प्रधान मंत्री जी ने इस पर ऑब्जर्वेशन दिया कि धारावाहिक चाणक्य की पूरी जितनी भी कड़ियां हैं, वह सब दिखलायी जाएं। तो मैं जानना चाहता हूं अंतिम प्रश्न के रूप में कि चाणक्य की कितनी कड़ियां दिखलायी गयी हैं, कितनी कड़ियां और दिखलायी जानी हैं और क्या इस संबंध में कोई आपत्ति हुई है और क्या कुछ कड़ियां इसमें कम की गयी हैं?

कुमारी गिरिजा व्यास : माननीय सभापति महोदय, जहां तक पहले प्रश्न का सवाल है, माननीय प्रधान मंत्री जी ने उस सदन में और इस सदन में जो एक बात कही थी कि कोई भी सरकार "शेडो" के अंतर्गत कार्य नहीं कर सकती है। कोई सरकार भी नहीं, कोई मंत्रालय भी नहीं और कोई व्यक्ति भी नहीं। इसलिए जो बार-बार आरोप लगाए जा रहे थे व्यक्तिगत रूप से भी और प्रेस में भी आया था, इसलिए मंत्रालय ने निर्णय लिया कि सारे मसले को सी०बी० आई० को सौंप देना चाहिए। अब जहां अभी-अभी आपने कहा कि कुछ सीरियल निर्विवाद थे, तो मैं यहां सिर्फ इतना याद दिला दूं कि not only Caesar but Caesar's wife is also above suspicion. इसलिए कुछ जो इस घेरे में आ जाते हैं, उसे उसका फल भोगना पड़ता है, लेकिन मैं यहां यह भी निवेदन कर दूं कि सी०बी०आई० के मेंबर्स को निवेदन कर दिया गया है कि मसला इतना पेचीदा नहीं है, मसला सिर्फ विवाद

का है ज्यादा पेचीदा नहीं है, इसलिए वे इस मसले को एक अलग मसले का रूप देते हुए, स्पेशल कैटेगरी मानते हुए इस संबंध में जल्दी निर्णय दें।

अब जहां तक चाणक्य का प्रश्न है, सभापति महोदय, चाणक्य को पहले 26 एपीसोड दिए गए थे और उसके बाद दूरदर्शन के एक ऑफिसर की गलती से एक पत्र इश्यू हो गया था जिसमें उसे 52 कड़ियां दे दी गयी थीं। सभापति महोदय, जिन सीरियल्स को कुछ लंबी कड़ियां दी जाती हैं या जो सीरियल्स बढ़ाए जाते हैं उसके पावर्स सिर्फ सेक्रेटरी के पास होते हैं, इसलिए केवल इसके रेक्टीफिकेशन के लिए कि यह पावर्स सेक्रेटरी के पास हैं, इसको रेक्टीफाय किया गया और चाणक्य को 47 कड़ियां और दे दी गयीं। सभापति महोदय, यहां मैं यह भी निवेदन कर दूं कि जब तक जिस चीज की सारगर्भिता होती है, जब तक ब्यूअरशिप होती है, निश्चित रूप से कड़ियों को बढ़ाया जाता रहा है।

श्री शंकर दयाल सिंह : प्रधान मंत्री जी ने इसमें रुचि लेकर, उन्होंने भी अपनी राय दी या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री सभापति : सीरियल देखने का उनको टाइम मिलता होगा बेचारों को?

SHRI AJIT KUMAR PANJA: There is no decision as such, but naturally the hon. Prime Minister.

श्री शंकर दयाल सिंह : प्रधान मंत्री जी, यही बता दें कि चाणक्य की कड़ियां वे देखते हैं या नहीं देखते हैं? उन्होंने देखी हैं या नहीं देखी हैं?

प्रधान मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : कड़ी नहीं, कुछ भी नहीं देखा टी.वी. में, कई महीने हो गए।

MR. CHAIRMAN: Look at the Government. The Prime Minister does not see the TV. Do you want him all the time before the idiot box?

SHRI DIPEN GHOSH: The Prime Minister doesn't see the TV because it is called the idiot box.

MR. CHAIRMAN: Do you want him all the time before the idiot box?

SHRI MURASOLI MARAN: Sir, he himself is a Chanakya. Then why should he see "Chanakya"?

SHRI G. Y. KRISHNAN: Sir, there are instances of applications for regional TV serials pending for a long time. I want to know from the Minister how many applications of such sort in Telugu and Tamil are pending. Sir, the applications are not acknowledged for several years. They are taking about two to three years for acknowledging and for their considerations. I want to know about it from the Minister.

SHRI AJIT KUMAR PANJA: Sir, this question does not arise out of this question. If the hon. Member wants to know, I will certainly ascertain how many applications are pending. But...

MR. CHAIRMAN: He wants to know how many applications are not acknowledged for two years.

SHRI AJIT KUMAR PANJA: In different regions...

MR. CHAIRMAN: Kindly find out.

SHRI AJIT KUMAR PANJA: It is find out.

SHRI SUKOMAL SEN: Sir, the things will be revealed only after the CBI inquiry is over. I am not going into that. By the manner in which the serials are shown on the TV, there are many reasons to believe that there is corruption in the selection of serials because sub-standard and meaningless serials find their way into the TV. I would like to know from the Minister whether they have laid down certain parameters and principles for the selection of serials, like moral, edu-

cational, entertainment national integration. What are the parameters? How are they selected? What is the mechanism so that some full-fledged measures are taken and in future a CBI inquiry is not required?

SHRI AJIT KUMAR PANJA: Sir, there are specific guidelines for sponsored programmes as well as commissioned progrmmes. The matters are decided according to the guidelines. In those guidelines, as it is known the rules of censor, Censor Board as such, have no place in the electronic media. But the rules are framed according to the law of the land, that is, no violence, no excessive sex matter to be shown in such a manner that it becomes...

SHRI SUKOMAL SEN: What is "executive sex matter."

SHRI AJIT KUMAR PANJA: The excessive sex matter is one when sex is shown in a vulgar way. (*Interruptions*) These are the guidelines.

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: Mr. Khushwant Singh in one of his serials has preached adultery. "He has stated in it that couples who are happily married are most boring and adultery is a must. But they should not talk about adultery with the other partner. Is it true?

SHRI AJIT KUMAR PANJA: It is not correct. (*Interruptions*).

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: I have got a copy of it.

SHRI. AJIT KUMAR PANJA: Sir, May I answer?

MR CHAIRMAN: I have not permitted him. You need not answer. You answer the question put by Shrimati Veena Verma.

श्रीमती वीणा वर्मा : माननीय सभापती जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि एक तरफ भी हमारे दूरदर्शन में भ्रष्टाचार और सी०बी०आई० इन्क्वायरी, यह सब चल रही है । तो सी०बी०आई० इन्क्वायरी की जांच रिपोर्ट कब तक आ जायेगी ? दूसरी तरफ हमारे दूरदर्शन को खतरा स्टार टी०वी० का है, जो कि अगस्त से शुरु होने वाला है, उसका हिन्दी चैनल शुरु हो जायेगा, तो ऐसे में जब कि दूरदर्शन हमारा अभी भ्रष्टाचार या सी०बी०आई० जांच में फंसा हुआ है, अभी सलेक्शन नहीं हुआ है, हमारे पास कोई प्रोग्राम, आगे के लिये कोई प्रोग्राम नहीं है और दूसरी तरफ खतरा हमारे दूरदर्शन के अस्तित्व का है, उसको विज्ञापनों से जो आय होती है, उसका है, तो हमारा टी०वी० दूरदर्शन स्टार टी०वी० के मुकाबले में खड़ा रहे और उसका ज्यादा रेवेन्यू आती रहे, इसके लिए आपकी स्पैसिफिक योजनायें क्या हैं ? और यह जो टी०वी० सीरियल का, जो भ्रष्टाचार का मामला है, सी०बी०आई० जांच चल रही है, कब तक यह जांच पूरी हो जायेगी ?

कुमारी गिरिजा व्यास : माननीय सभापति महोदय, सी०बी०आई० को डेस-लाइन नहीं दी जा सकती, उससे सिर्फ निवेदन किया है कि इस मसले को जैसा कि मैं उत्तर भी दे चुकी हूं कि इस मसले को, जल्दी से जल्दी निपटायें क्योंकि यह बहुत अधिक पब्लिक इंटरेस्ट का मसला है । यहां तक दूसरा प्रश्न है, जो हम सबको, प्रधान मंत्री जी से लेकर एक लेमैन तक को निश्चित रूप से थोड़ा सा परेशान किये हुए हैं कि बाहर से आने वाला स्टार टी०वी० आदि के मुकाबले हमारा दूरदर्शन किस प्रकार अच्छे कार्यक्रम दे । वैसे, महोदय, हम लोग अधिक इससे इसलिये चिन्तित नहीं हैं कि बाहर का सामान कितना भी दें, इस देश की अस्मिता और इस देश की संस्कृति ऐसी ही है कि वह बाहरी चीजों से अधिक प्रभावित नहीं हो सकती और मैं अधिकांशतः उदाहरण देती हूं कि तीन दिन हमें मान लीजिये, चाईनीज फूड खिला दिया जाये, लेकिन चौथे दिन हम अपनी दाल रोटी पर उत्तर आते हैं...

श्री सभापति : इसको क्यों ला रही हैं, इसमें ...(**व्यवधान**) ...

कुमारी गिरिजा व्यास : और इस तरह की सूचनायें भी प्राप्त होने लगी हैं, महिलाओं से विशेष तौर पर हमें आग्रह होने लगा है कि हमने यहां पर स्टार टी.वी. के केवल लिये हैं, हम उससे उकता गये हैं .... लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे लिए चुनौती की है कि हमारे कार्यक्रम अच्छे हों ताकि व्यूअरशिप हमारे कार्यक्रमों की बढ़ सकें।

श्री सभापति : इसके लिये कुछ आप कर रहो हैं, यह पूछ रही थी ?

कुमारी गिरिजा व्यास : जहां तक तीसरे प्रश्न का सवाल है .. (**व्यवधान**) ....

श्रीमती वीणा वर्मा : उस चुनौती को कैसे आप कम्पीट करेंगे और विज्ञापनों की दर भी कम हो जायेगी।

कुमारी गिरिजा व्यास : अभी 32 सीरियल एक वर्ष में करीब 70, बहुत से सीरियल चाहिये। हमारे पास अभी 32 सीरियल मौजूद हैं, इसके अतिरिक्त 6 कमीशन्ड कार्यक्रम में, वे पेंडिंग में है। तो पूरी हमारे पास तैयारी है कि हम उस चुनौती का सामना कर सकें और विज्ञापनों की अच्छी दरें प्राप्त कर सके।

श्रीमती वीणा वर्मा : विज्ञापनों की आय जो कम हो जायेगी, उसके बारे में नहीं कहा आपने।

कुमारी गिरिजा व्यास : आय कम इसलिये नहीं होगी कि 32 हमारे पास सपोंसर्ड सीरियल पेंडिंग हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मंत्री महोदय ने जब माना है कि सी.बी.आई. के अन्डर दिया गया है, इसका अर्थ यह है कि उसमें कुछ न कुछ कम्पलीट गड़बड़ी मंत्रालय द्वारा स्वीकार की गयी है। मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की गड़बड़ी आई कि जो सीरियल प्राइवेटली बनते हैं, उनमें आपके स्टुडियों का ही इस्तेमाल किया जाता है ? नम्बर दो – क्या आपके पास यह भी शिकायत आई है, कहीं से कि जितने रिटायर्ड आफिसर्स हैं, वे एक न एक सीरियल के पीछे रहते हैं या ले-देकर काम करा लेते हैं ? नम्बर तीन– कमीशण्ड प्रोग्राम और सपान्सर्ड प्रोग्राम, इन दोनों में से आपके पास किसकी शिकायतें ज्यादा आई है ? कमीशण्ड प्रोग्राम में आई या सपोंसर्ड प्रोग्राम में आई? अगर कमीशन्ड प्रोग्राम में आई, तो उसका अफेक्ट दूसरा होगा। अगर सपोसर्ड प्रोग्राम में आई तो उसका अफेक्ट दूसरा होगा। Am I clear?

श्री सभापति : वह सब समझ लिया है, उन्होंने।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : नम्बर दो।

श्री सभापति : नम्बर दो। It is wonderful और लोग भी इंतजार कर रहे हैं।

श्री प्रमोद महाजन : सैकिण्ड चैनल।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : कितना पैसा पिछले एक साल मे कमीशण्ड और सपोंसर्ड प्रोग्राम को दिया गया, क्योंकि भ्रष्टाचार का आधार पैसा ही है ? तो यह मेरे तीन-चार सवाल हैं ?

SHRI AJIT KUMAR PANJA: Sir, as for reasons for sending this enquiry to the CBI, on 29th August, 1991, 3rd September, 1991 and 4th September, 1991, in this august House, hon. Members, particularly, Mr. Kapil Verma, Mr. Vithalbhai Patel and Mr. David Ledger, made a specific complaint of corruption in Doordarshan. Sir, when this Government came into power in June, a specific complaint was made and for three days, the debate took place in this House. I said at that time, "Kindly give me specific instances, that is, not generally corruption, but one or two names." No name was given at that time. But later on, some newspapers carried certain names. Although we do not start an enquiry on a newspapers report, certainly it is a piece of evidence. So we made a Departmental enquiry through

a senior officer to find out whether these were correct or not and the hon. Members' speeches were also sent. They made a preliminary enquiry. After the report was submitted about 477 serials being approved they found that there were irregularities apparently in that. But it was already found that there was no necessity for sending that to the CBI. Apparently, from the record, it transpired that some of the serials which were in the approved list had been erased, some other names were put in and the names from the approved list were taken to a deferred list, a pending list. Now when the persons who had erased the names were asked, they said that there was a mistake and that was why erasure was made. On the preliminary enquiry, this came out to be in at least eight instances. Now when it became eight instances, the enquiry report was placed before me. I found that the Enquiry Officer also commented that he had submitted the report and that was only the tip of the iceberg. The serial numbers also have been changed. Then I thought that it was a fit case, that there was *prima facie* evidence, and I felt that it was a fit case for being sent to a specialised agency and that is the CBI whose independence we do not question and it was so sent. So far as the question of retired officers is concerned, no complaint has come to my knowledge. But, certainly, when a Member is raising this question, if the Member can send the name of any retired officer in charge of this, responsible for this bungling, I will immediately sent it directly to the CBI. Or, if the honourable Member himself, as a very responsible person can send it direct to the CBI in writing saying that this is the person whose name is not above suspicion, we can do so.

MR. CHAIRMAN: Mr. Bekal Utsahi.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : यह नहीं बताया कि जो शिकायतें आई हैं, वह कमीशण्ड प्रोग्राम्स की आई हैं या सपोंसर्ड प्रोग्राम्स की आई हैं ?

MR. CHAIRMAN: Mr. Mathur wanted to know about the commissioned programmes.

SHRI AJIT KUMAR PANJA: I am sorry, Sir. I could not answer that. Sir, a sort of rumour is being spread. Those who want to stifle the CBI inquiry say that this has been done by the Government in order to give encouragement to the commissioned category. This is absolutely incorrect. Already in the pipeline, as my learned colleague has answered just now, the amount of material remaining as approved prior to these sponsored schemes will take us up to March 1993. Therefore, there is no question of suppressing anything or encouraging any commissioned thing. That sort of propaganda is being made by a vested interest group and, Sir, I can assure this House that this Government will take it up to the bottom of the inquiry in order to see that the Doordarshan is cleansed and the people do get justice.

श्री बेकल उत्साही : हुजूर वाला मंत्री महोदय ने अपने जवाब में तफसील का इमकान रखा है।

†[ ]

श्री सभापति : जरा छोटा प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री बेकल उत्साही : बहुत छोटा प्रश्न पूछता हूं।

टी.वी. की अहमियत और उसकी बुसुसियत का अंदाजा इससे हुआ कि हमारे मुल्क के जहीन और निहायत ही अजीज तरीन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि बहुत अरसे से मैंने टी. वी. देखा ही नहीं। तो यह खुशी की बात हुई। इसलिय कि... (व्यवधान)..

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सीरियल्स के भ्रष्टाचार की जांच के लिये तो सी.बी.आई. को आपने बैठा दिया लेकिन यह नहीं बताया कि जो भ्रष्टाचार में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ एफ.आई.आर. तो दर्ज की गई लेकिन उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया ? पहले उनको सस्पेंड करत और फिर बाद में आप इन्क्वायरी कराते ।

मैं पूछना चाहता हूं अपने मंत्री महोदय से कि सीरियल्स तो आपने बन्द कर दिये, कमीशन बेस पर आपने कितने बनाय यह बात जनता में आम तौर पर मशहूर हैं और शोहरत पाती जा रही है कि आप कमीशन बेस पर बना रहे हैं। तो कितने ऐसे सीरियल हैं जो आप बनाने जा रहे हैं और बनाकर के जनता के सामने पेश करेंगे ? कहना यह है कि हमारे मंत्री महोदय ने अभी तो बताया है तफसील से लेकिन कमीशन बेस की तरफ वे नहीं आये हैं । मैं पूछना चाहता हूं उनसे और इसी शेयर से वह इसका जबाब दे दें:—

सुलगते शोलों में फूलों का आशियाना है;
बताओ अब के बरस किस तरफ निशाना है ?

श्री बेकल "उत्साही" : बहुत छोटा सा प्रश्न पूछता हूं।

टी.वी. की अहमियत और इसकी लोकप्रियता का अन्दाजा इस से लगाया जा सकता है कि हमारे ज़हीन और निहायत ही अजीज़ तरीन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि बहुत अरसे से मैंने टी.वी. देखा ही नहीं। तो यह खुशी की बात होती इस लिये कि... "मदाखलत

तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सीरियल्स के भ्रष्टाचार की जांच के लिये तो सी.बी.आई. को आपने बैठा दिया लेकिन यह नहीं बताया कि जो भ्रष्टाचार में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ एफ.आई.आर. तो दर्ज की गई लेकिन उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया ? पहले उनको सस्पेंड करत और फिर बाद में आप इन्क्वायरी कराते ।

मैं पूछना चाहता हूं अपने मंत्री महोदय से कि सीरियल्स तो आपने बन्द कर दिये, कमीशन बेस पर आपने कितने बनाय यह बात जनता में आम तौर पर मशहूर हैं और शोहरत पाती जा रही है कि आप कमीशन बेस पर बना रहे हैं। तो कितने ऐसे सीरियल हैं जो आप बनाने जा रहे हैं और बनाकर के जनता के सामने पेश करेंगे ? कहना यह है कि हमारे मंत्री महोदय ने अभी तो बताया है तफसील से लेकिन कमीशन बेस की तरफ वे नहीं आये हैं । मैं पूछना चाहता हूं उनसे और इसी शेयर से वह इसका जबाब दे दें:—

सुलगते शोलों में फूलों का आशियाना है;
बताओ अब के बरस किस तरफ निशाना है ?

MR. CHAIRMAN: You also recite some poetry!... (*Interruptions*)...

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

SHRI AJIT KUMAR PANJA: Sir, I know only one such thing:

क्या पूछते हो मेरे कारोबार का,
आइने बेचता हूं अंधों के शहर में।

Sir, the honourable Member has asked why we have not gone in for suspension. Sir, whenever the Government wants to take any strong action, we have to be very careful because strong power has to be utilized. Even then, Shrimati Nirmal Verma, the lady who was directly in charge, during the time of the inquiry made certain statements. She is a Controller of Programmes and she was put under suspension forthwith, although with great pain. We did not wish to do it, but we have done it... (*Interruptions*)...

Now, so far as the commissioned programmes are concerned, as I have said, this is a propaganda, it is a false propaganda being made by certain vested interests. There is no such thing whatsoever. The sponsored serials already remaining approved prior to this scheme are 32 in number which will take us up to March, 1993. Commissioned serials, already approved prior to the new commissioned scheme, are 6 which are remaining in the pipeline. And, therefore, it is not correct, Sir, as tried to be made out by some vested interests, that we have stayed the sponsored serials only to give effect to the commissioned programme and pay money. That is not correct, Sir.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, I have no hesitation in complimenting the Minister for ordering an immediate CBI inquiry because I believe that there have been rampant complaints about the serials, about the way the serials are being put through, about the way the serials have been allowed to be screened. Therefore, while complimenting the Minister for ordering a CBI inquiry, I would like to know from him that in view of the serious assault that the country faces because the Cable TV and other TVs from the western world which is a serious assault on the intellectual environment of the country, it is not only necessary...

MR. CHAIRMAN: Put your question, please. Half an hour has gone already.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I am putting the question, Sir. I would like to know as to what steps the Government contemplates to take to improve the standard of the serials in the country. And part (b) of my question is that while the CBI has been asked to probe, there has to be a timeframe. The CBI cannot be allowed to drag on the issue endlessly because the root must be eradicated. Therefore, what about updating? And what is the timeframe?

SHRI AJIT KUMAR PANJA: Sir, so far as the quality of the serials is concerned, we have already started taking steps. Sir, five years ago, there was a procedure when I was in this very Department of registering well-known producers. Somehow or the other, the Government which came in later on in 1990 got rid of that procedure and made it open to all which created a lot of confusion and dilution of value which is so much required in serials, cinemas and others, as the hon. Member knows. So, we are thinking of having a registry of already established producers/directors so that this quality of the sponsored serials or commissioned serials improves. Along with that, Sir, we have already about 60 non-Government persons who take part in the selection. We will have a look at it. My colleague is going in detail of each one's bio-data so that the best of the persons could be taken for advising the Government about the quality of the serials. Sir, so far as the timeframe to the CBI is concerned, we cannot give any timeframe. But certainly we have mentioned in the letter that this is a special inquiry and should be disposed of expeditiously.

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : चेयरमन सर, इस अखबार में मंत्री महोदय के खिलाफ इलजामात हैं। क्या ये इनके नोटिस में आया है... **(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप प्रश्न कर लो ना।

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : इसी बारे में ये लाल हाशिय की खबर है चयरमन सर, वरी इम्पोर्टेंट --- "दूरदर्शिनी भ्रष्टाचार

में पंजा भी और भगत भी" और श्री भगत की.... (व्यवधान)

श्री सभापति : लाठर जी आप सवाल कर लो ना... (व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : मैं सवाल ही करने लगा हूं। ये क्या मंत्री महोदय के नोटिस में दैनिक जागरण के अखबार की 12 तारीख की खबर आई है, जिसमें कि मंत्री महोदय पर और फार्मर्मीनिस्टर भगत पर इलजामात लगाये है कि वह इस घपले के अन्दर शामिल है और इसके अन्दर श्री भगत की चिट्ठी भी छापी गई है। इस अखबार के अन्दर इलजाम लगाया है। आपने पूछा था कि स्पैसिफिक इंस्टेंस बताइये। आंध्र प्रदेश के चार फिल्म मेकर्स ने आठ-आठ लाख रुपया देकर अपने सीरियल के लिय पेमेंट किया है..... (व्यवधान) क्या ये आपके नोटिस में है.. (व्यवधान)

श्रीमति सत्या बहिन : भगतजी का नाम ले रहे हैं जो इस हाऊस के मेंबर नहीं है और दूसरा ये अखबार का रेफेंस दे रहे हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है .... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसमें छपा क्या है .... (व्यवधान).. सर इन्होंने खुद ही छपवाया है... (व्यवधान)

श्रीमती सत्या बहिन : इन्होंने ठीक से पढ़ा ही नहीं है .. (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You don't take notice of it . जवाब दीजिए ..... (*Interruptions*) He is answering.

SHRI SURESH KALMADI: Sir, it should be taken off the record.

..SHRI AJIT KUMAR PANJA: Sir, this type of newspapers do not come usually to our notice. But the hon. Member himself mentioned it in the Zero Hour. Therefore, our people are posted here to find out what the hon. Members say. That has come to our notice and I have sent it to find out what the details are of it. Sir, as I said, a group of vested interests is working. If you take me about the complaints made, there are umpteen number of complaints made against the Ministers of the previous Governments also, the just preceding Government. I do not want to go into this. That political mud-throwing goes on. The CBI has been given full power. I assure the House that CBI is an organisation which gets full power to go into the details of every thing, and if the hon. Member feels that he is sure about any corruption charge against me, he can take the responsibility and write a letter to the CBI to go into it, and I will face that inquiry.

MR. CHAIRMAN: Next question.

Export of Pepsi Foods

*242. SHRI DIPEN GHOSH: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to refer to the reply to Unstarred Question 435 given in the Rajya Sabha on 30th April, 1992 and state:

(a) whether Government consider Pepsi Foods' exports from leased facilities as exports of their own manufactured goods towards the export commitment of 40 per cent;

(b) whether exports given as exports from select list are from products coming under appendix 16 of Export Import Policy April 1985—March 1988; and

(c) whether Pepsi Foods has met its export commitments so far as per the conditions of its foreign collaboration approval?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) to (c) The entire matter regarding fulfilment of export obligation by M/s. Pepsi Foods Limited has been referred to the office of the Chief Controller of Imports & Exports, Ministry of Commerce. The matter is *sub judice* before quasi-judicial authority in CCI&E organisation.

SHRI DIPEN GHOSH: Sir, on the 29th of August last year in reply to an Unstarred Question No. 633, the hon. Minister had stated that the matter was referred to the CCI&E, and the CCI&E